खट्टर द्वारा बूस्टर उद्घाटन के बावजूद पानी की आपूर्ति नहीं

फ़रीदाबाद (म.मो.) शिलान्यास व उद्घाटन के शौकीन हरियाणा के मुख्यमंत्री खट्टर ने 20 नवम्बर को थोक के भाव उद्घाटन करते हुए सेक्टर 22 के निकट स्थित मछली मार्किट में बने 22 साल पुराने जलघर के बूस्टर का बटन दबाकर उद्घाटन किया था। बटन भी दब गया, तालियां भी बज गई, खट्टर ने अपनी पीठ भी थपथपा ली और क्षेत्र की जनता पर एहसान का बोझ भी लाद दिया लेकिन खबर लिखे जाने तक यहां से एक बूंद पानी भी जनता को नहीं मिल पाई।

दुर्भाग्य की बात तो यह भी है कि करोड़ों रुपये की लागत से, 22 साल पहले बने जलघर को अभी तक किसी ने भी नहीं सम्भाला था। बीते 8 साल के खट्टर शासन ने भी इसकी सुध नहीं ली। बूस्टर का बटन दबाते वक्त खट्टर ने इस लापरवाही के लिये किसी की जवाब-तलबी नहीं की।

विदित है कि सेक्टर 22, 23 ,24 संजय कॉलोनी सेक्टर आदि-आदि की करीब 80 हजार आबादी को जलापूर्ति के लिये इस जलघर का नगर निगम द्वारा निर्माण किया गया था। इस निर्माण कार्य से निगम के भ्रष्ट एवं कमीशनखोर अधिकारियों तथा राजनेताओं का तो पूरा कल्याण हो गया लेकिन इलाके की जनता को कोई लाभ न हो पाया। खट्टर द्वारा उक्त उद्घाटन से क्षेत्र के लोगों को लगा था कि अब उनके घर में बिना मोटर चलाये टूटी घुमाते पानी बहने लगेगा। लेकिन हकीकत इसके विपरीत, मोटर चलाने से भी 72 घंटे में एक बार कुछ देर के लिये ही पानी आता है। जाहिर है पानी की इस नाममात्र आपूर्ति के भरोसे नहीं रहा जा सकता। ऐसे में लोगों को टैंकरों से पानी खरीदकर गुजारा करना पड़ता है।

Paytm

MM

Majdoor Morcha

UPI ID: 8851091460@paytm

8851091460

Scan this QR or send money to 8851091460 from any app. Money will reach in Majdoor Morcha's bank account.

केवल पाठकों के दम पर चलने वाले इस अखबार को सहयोग देकर अपनी आवाज को बुलंद रखें।

मज़दूर मोर्चा- खाता संख्या- 451102010004150

IFSC Code : UBIN0545112

Union Bank of India, Sector-7, Faridabad

घर बैठे प्राप्त करें मज़दूर मोर्चा

आज ही अपने हॉकर से कहें, कोई दिक्कत हो तो शर्मा न्यूज एजेंसी से फोन नं 9811159238 पर बात करें। बल्लभगढ़ के पाठक अरोडा न्यूज एजेंसी से 9811477204 पर बात करें।

अन्य बिक्री केन्द्र :

1. प्रिंट फोर्ट, टेलीफोन एक्सचेंज के सामने नेहरू ग्राउंड।
2. रेलवे बुक स्टाल ओल्ड रेलवे स्टेशन
3. एनआईटी रेलवे स्टेशन के बाहर बाटा चौक पुल के नीचे।
4. जितेन्द्र, बाटा सेंटर - 9971064207
5. मोती पाहुजा - मिनार गेट पलवल, 9255029919
6. सुरेन्द्र बघेल - बस अड्डा होडल - 9991742421

मज़दूर बस्ती नई भी हो, तब भी गंदगी कम नहीं होती; 'भारत कॉलोनी'

विजय सिंह एवं सत्यवीर सिंह

पिछली सदी के अंत तक, फ़रीदाबाद महानगर की पूर्वी सीमा, 'दिल्ली आगरा नहर' हुआ करती थी. 80 और 90 के दशक में, अर्थव्यवस्था के 'सेवा उद्योग' के क्षेत्र में आए उछाल से मिलने वाले लाभ के मामले में, फ़रीदाबाद के साथ गुडगाँव की तुलना में दुहांत हुआ. इसीलिए पूंजीवादी चमक-दमक के मामले में इस पक्षपात का असर, दोनों महानगरों में साफ़ नज़र आता है. 'वस्तु उत्पादन उद्योग' में आई मंदी भी इसका कारण रहा. इक्कीसवीं सदी की शुरुआत में, फ़रीदाबाद में एक महत्वाकांक्षी परियोजना बनी और 'नहर पार' क्षेत्र में हरियाणा सरकार ने, 'हरियाणा शहरी विकास निगम (हुडा) के माध्यम से, कई गांवों की ज़मीन अधिग्रहित की और 24 नए सेक्टर (66 से 89) बनाए. 'ग्रेटर फ़रीदाबाद' के नाम से अनेकों निर्माण योजनाओं पर काम शुरू किया. 66 से 74 सेक्टर औद्योगिक सेक्टर हैं, जबकि 75 से 89 आवासीय सेक्टर हैं.

इस सम्बन्ध में फरीदाबाद को 'जवाहरलाल नेहरू शहरी विकास निगम (JnNURM) के तहत आवश्यक धन उपलब्ध हुआ. इस सदी के पहले ही दशक में, भयंकर पूंजीवादी संकट के फलस्वरूप आई, वैश्विक अभूतपूर्व मंदी ने, इन परियोजनाओं की खूबसूरती छीनकर, इन्हें कुरूप बना दिया. घिसट-घिसटकर सरक रही परियोजनाएं लंबित हुईं, कुछ बंद ही पड़ गईं. कितने ही बिल्डरों के दिवाले निकले, कुछ जेल में हैं. अपने घर का ख़्वाब देख रहे मध्यवर्ग के मुंगेरी ख़्वाब भी टूटकर बिखरे. जाने कितने अवसादग्रस्त हुए. फिर भी 'नहर पार' आज का नया, चमकता फ़रीदाबाद है, इसमें दो मत नहीं.

कोई भी निर्माण हो, कैसा भी विकास हो, मज़दूरों के हाथों के बगैर नहीं होता, ये एक शाश्वत सत्य है. पूंजीवादी चमक-दमक, मज़दूरों का खून चूसकर ही आती है. इसी का नतीज़ा था कि जैसे-जैसे निर्माण परियोजनाएं ऊपर उठीं, मज़दूर बस्तियां भी बसनी शुरू हो गईं. इसी क्रम में बसी एक बस्ती है; 'भारत नगर', जो फ़रीदाबाद के सेक्टर 87 में पड़ती है. सेक्टर 28 पर नहर के पुल से शुरू हुई, मास्टर रोड के दक्षिण में और खेड़ी रोड के उत्तर में, फैली विशाल मज़दूर बसाहत 'भारत कॉलोनी' कहलाती है. इसके अधिकतर निवासी निर्माण मज़दूर और निर्माण कार्य से जुड़े 'स्व-व्यवसायी' हैं, जिन्हें मज़दूरों की श्रेणी में रखा जाना ही उचित है, भले वे खुद भी दो-चार मज़दूरों को मज़दूरी पर क्यों ना रखते हों. सीमांत किसानों की भांति, वे, मज़दूरों से भी ज्यादा श्रम करते हैं और उनके काम के घंटे भी तब तक रहते हैं, जब तक उनका शरीर साथ देता है. इस बस्ती के कुछ लोग, जिन्हें अपनी ज़मीनों का मुआवज़ा मिला था, बड़े आहातों वाले घरों में रहते हैं, और किसानी परंपरा के अनुसार गाय-भैंस भी पालते हैं. बिलकुल किसानी अंदाज़ में, वे, घर के दरवाज़े पर मूढा डालकर हुक्का गुड़गुड़ाते रहते हैं.

जिस दिन 'क्रांतिकारी मज़दूर मोर्चा' की टीम भारत कॉलोनी गई थी, उसके 4 दिन पहले बहुत मामूली बूंदा- बांदी हुई थी. बस्ती में चलते हुए लगा, मानो भारी बारिश होकर बस अभी रुकी है. 'सड़क' पर पैदल चलने के लिए, लगातार उसके दाएं कोने से बाएँ कोने तक, सड़क की चौड़ाई नापनी पड़ती थी. पानी के निकास की कोई व्यवस्था नहीं है. न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम के अनुसार, पानी, समतल सड़क पर वहीँ ठहरा रहता है, जो घर ऊँचे बने हैं, उनसे बहकर सड़क पर, तथा जो नीचे बने हैं, सड़क से उनकी दिशा में प्रवाहित होता रहता है.

सीवर की कोई व्यवस्था नहीं, इसलिए सड़क पर सीवर के पानी के भी गड्ढे बन गए हैं, जो गन्दगी से बजबजाते रहते हैं. मच्छर और बिमारियों के कीटाणु फलते-फूलते रहते हैं. अगर आप सोच रहे हैं कि सड़क पर चलना सिर्फ बरसात में ही दुश्वार होता है, तो आप ग़लत सोच रहे हैं. क्रांतिकारी जन-कवि 'पाश' की एक बहुत मक़बूल नज़्म की लाइन है, "सबसे ख़तरनाक होता है हमारे सपनों का मर जाना". मज़दूर बस्तियों में सबसे खतरनाक होता है, नाली बनाने और चौड़ा करने के लिए सडकों को तोड़ा जाना और उसे वैसा ही छोड़कर, भूल जाना. भारत कॉलोनी की मुख्य सड़क को फरवरी के महीने में तोड़ दिया गया था कि इसे चौड़ा किया जाएगा और सीवर लाइन बिछेगी. आज तक वो वैसी ही टूटी पड़ी है. निर्माण कार्य, नाम मात्र के लिए भी, कहीं शुरू नहीं हुआ है. क्या वज़ह है, किसी को नहीं मालूम. शायद नगर निगम चुनाव का इंतज़ार है. आखिर, चुनाव के वक़्त, डबल इंजन सरकार का विकास भी तो दिखाना है! नगर निगम में कोई फोन नहीं उठाता. यहाँ मिटटी थोड़ी रेतीली है, इसलिए हर वक़्त धूल उड़ती रहती है. सीवर के पानी की गन्दगी से पैदा हुए कीटाणुओं से भी अगर कोई बीमार ना पड़ रहा हो तो, उसकी इम्युनिटी उसके फेफड़ों में जमी धूल से टेस्ट हो जाएगी!!

भारत कॉलोनी, हनुमान नगर और इंदिरा कॉम्प्लेक्स एक साथ मिले हुए हैं, और इन बस्तियों की कुल जनसंख्या 40,000 से कम नहीं होगी. हालाँकि कुल कितने राशन कार्ड या वोटर कार्ड हैं, ये जानकारी नहीं मिल पाई. बस्ती की सबसे मूलभूत समस्या है; यहाँ नगर निगम के पानी की आपूर्ति है ही नहीं. क्या कोई सोच सकता है कि इतनी बड़ी बस्ती में पानी की सप्लाई नहीं है!!

अधिकतर घरों में सब-मरसिबल बोरिंग हैं. जिन लोगों की हैसियत, ऐसे खर्चीले बोरिंग कराने और निजी पंपसेट मोटर रखने की नहीं है, वे या तो पैसे देकर पानी ख़रीदते हैं, या बोरिंग वालों की अप्रत्यक्ष, आंशिक गुलामी या बेगार झेलने को मज़बूर हैं.

पानी की ये व्यवस्था बहुत मंहगी है, 25,000 तक खर्च हो जाता है. दूसरी समस्या ये है कि ज़मीन का पानी लगातार प्रदूषित होता जा रहा है. पानी का प्रदूषण गहराई तक होता जा रहा है. इस पानी का अगर टेस्ट किया जाए तो गंभीर हानिकारक अवयव पाए जाएँगे, लेकिन ज़द्दोज़हद अगर किसी भी तरह आज जिंदा रहने की हो, तो धीमी मौत की परवाह कौन करे? जो बरदाश्त कर सकते हैं वे बिमारियों से बचाव के लिए 20 लीटर वाले बिसलेरी के केन ख़रीदने को मज़बूर हैं.

एक मज़दूर साथी ने, जो वहां 15 साल से रह रहे हैं, क्रांतिकारी मज़दूर मोर्चा को बताया कि बस्ती में एक भी सरकारी स्कूल नहीं है. मज़दूरों के बच्चों को शिक्षा से क्या मतलब!!! तालीम नहीं पहुंची, लेकिन बस्ती में कई तरह के 'भगवान' पहुँच चुके हैं, और सभी आबाद हैं. 'मातारानी के जगराते' ज़ोर-शोर से होते हैं. मज़हबी ख़ुराक की कोई किल्लत नहीं. कोई सरकारी डिस्पेंसरी भी नहीं है. सामुदायिक केंद्र नहीं, बच्चों को खेलने के पार्क नहीं, सार्वजनिक शौचालय नहीं. इन सुविधाओं के लिए जन-जागरण करने वाले, सामाजिक-राजनीतिक संगठन भी नहीं. लोगों का गुस्सा वहीँ आपस में एक-दूसरे पर फूटता रहता है.

नहरपार के नए फ़रीदाबाद, ग्रेटर फ़रीदाबाद में, मॉडर्न दिल्ली पब्लिक स्कूल आया, कई चमचाते व्यवसायिक संस्थान आए, आधुनिक मार्केट, मॉल आए, 'ओमेक्स वर्ल्ड स्ट्रीट' आया, लेकिन मज़दूरों के हिस्से वही गन्दी झोपड़ियाँ, धूल उड़ाती टूटी सड़कें, बजबजाती नालियों पर मच्छरों के बादल और कीटाणु ही आए. 2600 बिस्तर वाले एशिया के सबसे बड़े 'अमृता अस्पताल' का उद्घाटन 28 अगस्त को मोदी जी ने यहीं पास में किया था. लोग उसे 'मोदी हॉस्पिटल' बोलने लगे हैं. वहां ओपीडी में अब तक शुल्क तो कम है, 276 रुपये, लेकिन परीक्षणों के पैसे अलग से लिए जाते हैं. मज़दूर इसीलिए उससे दूर ही रहते हैं. ओपीडी फ़ीस भी क्या पता, दूसरे अस्पतालों के ग्राहक तोड़ने के लिए ही अभी कम है, जैसे जिओ ने शुरू में बहुत सस्ती मोबाइल सेवा उपलब्ध कराई थी, आज पिछला भी वसूल रहा है. वहां का स्टाफ़ कहने लगा है कि अगले साल से यहाँ की फ़ीस भी बाज़ार से ही तय होगी.

नागरिक सुविधाएँ नहीं हैं, आप लोग लड़ते क्यों नहीं? इस सवाल का जवाब ये मिलता है कि सरकार कहती है कि 'ये कॉलोनी अवैध है'. लम्बी-लम्बी, बे-सिरपैर की छोड़ने वाले, लच्छेदार डींगें हांकने वाले हुक्मरानों से कोई पूछे कि सारे देश में कोई जगह बताई जाए, जहाँ देश की 100 करोड़ मेहनतक़श आबादी अपना वैध घर बना सके. 'जहाँ झुग्गी, वहीँ पक्का घर' जुमला तो चुनावों के सीजन के लिए आरक्षित है. शहरों की तो छोडिए, वहां तो मध्य वर्ग भी मकान नहीं खरिद सकता, सुदूर गाँव में भी रहने लायक़ पक्का 'वैध' घर बनाने की हैसियत मज़दूरों की नहीं रही. ये लोग क्या करें? कहाँ जाएँ? इन सवालों के जवाब, मज़दूरों के घरों को 'अवैध' बताने वाले हुक्मरानों के गिरेहबान में हाथ डालकर पूछे जाने चाहिएं. वह, लेकिन, तब ही संभव होगा जब मज़दूर संगठित होंगे, जागरुक होंगे, वर्ग चेतना से लैस होंगे. और वह जल्दी ही होगा.